पाए गए दोषी अधिकारियों के खिलाफ समुचित कार्यवाही की जाये, जिससे भविष्य में इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं पुनः न घट सकें ।

18.17 hrs.

[SHRI K. RAJAMALLU *in the Chair*]

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विक्रम महाजन) : माननीय चेअरमेन, साहब, मैंने दिल्ली में बिजली जाने के बारे में एक स्टेटमेंट दे दिया है । मैंने यह बताया है कि यह ब्रेकडाउन देहर से पानीपत लाइन में एक ट्रिपिंग की वजह से हुआ था । यह एक इम्पार्टेंट लाइन है जो कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यू० पी०, दिल्ली सभी को कनेक्ट करती हैं । इसमें पानीपत के पास एक टेक्नीकल डिफेक्ट हुआ इसकी वजह से दिल्ली में ब्लेक आउट हुआ । हमने थोडे से समय में ही कुछ मशीनरीज के डिफेक्ट को दूर करके बिजली को रेस्टोर कर दिया ।

जहां तक दिल्ली में पावर सिचुएशन का ताल्लुक है दिल्ली में पावर सिचुएशन पिछले दिनों में बहुत अच्छी रही हैं । मार्च, 1979 में जबकि इनकी सरकार थी सात दिन लोड शेडिंग हुआ जबकि इस साल एक दिन भी नहीं हुआ । अप्रैल, 1979 में जबकि इनकी सरकार थी 9 दिन लोड शेडिंग हुआ इस साल कोई भी नहीं हुआ । कल जो हुआ इसकी वजह ग्रिड में डिफेक्ट होना था । हमने इंक्वायरी आर्डर कर दी है । हमारे जितने टेक्नीकल मेम्बर हैं वे इसका पता लगायेंगे कि यह फेल्योर क्यों हुआ । यह बात मैंने स्टेटमेंट में मैं भी कह दी हैं । इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि वहां क्या टेक्नीकल रिक्वायरमेंटस हैं जिससे कि दुबारा यह रिपीटीशन न हो । यह प्योरेली टेक्नीकल मामला है । यह सब मैंने स्टेटमेंट में भी बताया है ।

श्री मनीराम बागड़ी । अगर पिछली सरकार कत्ल करे तो आपको भी कत्ल करने की छुट्टी है ? अगर पिछली सरकार ने पाप किया तो क्या आप भी पाप करेंगे ? अगर पिछली सरकार के वक्त में दस दिन बिजली नही आयी तो आप को भी इसके लिए माफी दे दी जाए ? इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है, पिछली सरकार जिम्मेदार नही । पिछली सरकार बुरी थी इसलिए आप भी बुरा होना चाहते हैं ?

(ii) HARMFUL EFFECTS OF INDISCRIMINATE USE OF POISONOUS CHEMICAL PESTICIDES

*SHRI RASABEHARI BEHERA (Kalahandi): Efforts are being made all over the country for increasing agricultural production and with that end in view the newly developed high yielding varieties of crops have been introduced extensively. Additional quanti ies of fertilizers and chemical pesticides are necessarily used in the fields where such high yielding varieties of seeds are sown. Proper instructions are always written on the cover of the packets and tin containers of these chemical pesticides about the method of their use in the fields. But the Indian farmers who are generally illiterate, find it extremely difficult to understand these written instructions.

A few years back one of the research organisations of San Francisco of USA had cautioned the farmers all over the country about the harmful effects of the use of chemical pesticides in farming. This organisation was of the view that the indiscriminate use of chemical pesticides was the root cause of a large number of new diseases and deaths caused there-

*The original speech was delivered in Oriya.

by. In view of the above mentioned dangers inherent in the use of such pesticides, the Government of India should send circulars to the farming communitees warning them not to use the chemical pesticides without proper precaution and care. It may be recalled that the former USA President had banned the export of chemical pesticides by the various trading companies of USA which were harmful and poisonous. He had cautioned the farmers all over the world against the use of those pesticides. In view of this, I request that the Government of India should take every precautionary measure for not using such harmful and poisonous chemical pesticides.

Even water kept in the clean tins and plastic packets earlier used for containing pesticides has been found to be contaminated. Since most of the farmers are illiterate the Government should immediately impose restrictions on use of such poisonous chemical pesticides. I demand that the Government should set up a research laboratory in each State and these chemical pesticides should be examined thoroughly in the laboratory before sending to the fields.

(iii) NEED TO ACCORD TRADE UNION RIGHTS TO THE WORKERS WORKING IN THE INDUSTRIAL BELT OF MIRZAPUR, U.P.

SHRI NARAYAN CHOUBEY (Midnapore): In the industrial belt of Mirzapur in Uttar Pradesh in places like Renukut, Benusagar, Saktinagar, big factories like Hindalco exist and also big power plants are being constructed, and big coal mines are functioning. These power projects belong to the public sector and belong to the Central Government as well as the State Government. The coal mines are owned by the Central Government. In this area there is absolutely no right for the workers to function and organise their trade unions. In the entire belt Section 144 is enforced for more than 16 months at a stretch. The union specially cannot hold any public meeting or demonstration since permission is rarely granted to them. Restrictions on meetings and demonstrations are projects in collusion with the local administration. Even ordinary gate-meetings are not allowed to be held at the gates of Hindalco and Renusagar Power Projects. The local administration is controlled by the management and in factories and projects at their behest the police openly terrorise the workers and very often beat them and start false cases against them. The Central Government should immediately enquire into the whole matter and see that rule of law prevails there and industrial workers are not treated as bonded labourers and slaves as they are also employees of the public sector belonging to the Central Government.

(iv) Need to provide coal and lignite to brick kiln manufacturers of Gujarat.

श्री मोती भाई आर० चौधरी (मेहसाना) : गुजरात मे इंटे पकाने के लिए स्लैक कोल और लिगनाईट न मिलने की वजह से ईट उद्योग में भारी रुकावट आई है। सिर्फ अहमदाबाद में ही ईट उत्पादन में 40 प्रतिशत की कमी हो हो रही है। कई ईट पकाने वाले कारखाने (भट्टे) बंद हो गए हैं जिससे कि 15 से 20 हजार मजदूर बेकार हो गए हैं अर्थात बेरोजगार हो गए हैं। मिलों और कोयले से चलने वाले कारखानों से जो कोयले की राख निकलती है यह ज्यादातर ईट पकाने के उपयोग में आती है लेकिन बढ़ती हुई ईटों की मांग को देखते हुए यह राख पर्याप्त मात्रा में ईट पकाने वाले कारखानों को नहीं मिल रही है। राख की मांग ज्यादा होने के कारण इसके दामों में 2 से 3 गना तक की वृद्धि हो गई है जिससे ईटों के भाव भी बढ़ रहे हैं। ब्रिक मेनीफेक्चरर्स एसोसिएशन ने बार बार माग की है कि गजरात में कच्छ में जो लिगनाईट वर्तमान में मिल रहा है यह ईट उद्योग को दिया जाए क्योंकि स्लैक कोल मिलता नहीं है और लिगनाईट भी नहीं मिल रहा है। अब मानसून भी आने वाला